SHRI SHARAD PAWAR: Practically, we have communicated with all the States. It is their responsibility to issue the ration card, whether it is AAY or whether it is BPL. Guidelines have also been given to them. If there is a specific complaint about any district, any city or any State, and if I get that information, I will happily take it up with the respective State Government and take corrective action.

श्री दत्ता मेघे: सर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है, जहां गेहूं और चावल कम होता है। खास तौर पर वहां के जो आदिवासी एरियाज़ हैं जैसे Melghat, Garhchiroli, आदि, वहां बाल मृत्यु बहुत होती है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं, क्या हम उनको अनाज नहीं दे सकते हैं ऐसे जो जिले हैं, जहां बाल मृत्यु हो रही है और जहां अनाज नहीं जा रहा है, वहां इन लोगों को स्पेशल अनाज मिले, क्या केन्द्र सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है?

श्री शरद पवार: सर, वहां के दो-तीन डिस्ट्रिक्ट्स की जो स्थिति यहां बताई गई है, तो महाराष्ट्र के दो-तीन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में यह स्थिति है और राजस्थान के भी दो-तीन डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी परिस्थिति है। वहां के लिए एक अलग कोटा, ज्यादा कोटा कम कीमत पर देने का डिसीज़न इससे पहले ही गवर्नमेंट ने लिया है और इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा एलोकेशन दिया जाता है।

श्री सभापति: नेक्स्ट क्वेश्चन।

Curbing the rising prices of pulses and other food items

*82. SHRI AMAR SINGH:
SHRI JAI PARKASH AGGARWAL:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the prices of pulses and other food items including vegetables have risen abnormally which are beyond the reach of lower middle class people;

(b) if so, the details thereof and the specific reasons for the increase despite bumper crop of wheat and sugarcane in the country during the current year, and

(c) the action Government have taken to curb the price rise and the result thereof?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The prices of certain essential commodities such as wheat, sugar and pulses registered an upward trend during the past few months. During 2005-06, production of wheat is estimated to be 69.48 million tonnes, as against 68.64 million tonnes in 2004-05 and 72.15million tonnes in 2003-04. The production of pulses is estimated at 13.11 million tonnes in 2005-06 as against 13.13 million tonnes in 2004-05 and 14.91 million tonnes in 2003-04. The production of sugarcane during 2005-06 is estimated at 278.39 million tonnes as compared to production of 237.09 million tonnes in 2004-05 and 233.86 million tonnes in 2003-04. The reasons for rise in prices of food items are shortfall in domestic supplies relative to demand and hardening of international prices.

(c) Government has already taken steps to arrest the increase in prices by taking measures such as augmenting domestic supplies through imports at reduced duty rates, ban on exports of pulses and sugar and regular monitoring of prices of essential commodities. Other steps taken include advice to State Governments to initiate steps to ensure availability of essential commodities at reasonable prices. These steps taken by the Government have generally stabilized the prices.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सभापति महोदय, हर साल यह समस्या आती हैं इस बार दालों के दाम तकरीबन 20 रुपए से 50 रुपए किलो तक पहुँच गए। इससे लोगों को बहुत परेशानी हुई। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब पिछले 5-7 सालों से बराबर यह तकलीफ हो रही है, तो क्या सरकार ने कोई ऐसा सर्वे कराया है, जिससे यह पता लगे कि जहाँ यह पैदावार होती है, वह पैदावार बन्द क्यों हो गई? सर, उसकी मेन वज़ह यह है कि जहाँ पैदावार होती थी, वहां पल्सेज़ की जगर सोयाबीन की पैदावार होने लगी, जो कैश क्रॉप मानी जाती है उसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं और सिवाय इम्पोर्ट करने के कोई दूसरा चारा नहीं है। मैं सीधा सवाल करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने इस ओर ध्यान दिया कि जो commodities कम हो रही हैं, उनकी क्रॉप क्यों कम हो रही है? इसकी क्या वजह है? अगर उनकी क्रॉप कम हो रही है तो आप उन किसानों को क्या फैसिलिटी देना चाहते हैं, ताकि वे उसे छोड़ कर किसी दूसरी क्रॉप पर नहीं जाएँ?

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है। हो गया। ...(**व्यवधान**)...

श्री जनेश्वर मिश्र : अगर दाल में पानी ज्यादा मिला दें, तो सब का काम चल जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : और उसे पीने के लिए आपको बिठा दें। ...(**व्यवधान**)...

श्री जनेश्वर मिश्र: वह सूप की तरह पिया जा सकेगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद पवार: सर, जहां तक पल्सेज़ की बात है, माननीय सदय ने जो कहा, यह बात सच है कि पिछले कई सालों से हमारे देश में पल्सेज़ का उत्पादन एक स्टेग्नेशन के लेवेल पर है। इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इसका मुख्य रीज़न यह है कि अपने देश मे पल्सेज का टोटल क्रॉप रेन फेड एरिया में लगाते हैं, इरिगेटेड एरियाज़ में पल्सेज का काम नहीं करते। इसलिए इसका यील्ड एक लिमिटेड लेवल पर है।

दूसरी बात कि हमारे देश में Indian Council of Agricultural Research के माध्यम से आज कई नई वेरायटीज़ आई हैं। मगर पल्सेज़ के क्षेत्र में इतना अच्छा ब्रेक थ्रू अभी तक नहीं मिला, यह बात सच है। कुछ नई वेरायटीज़ डेवलप की गई हैं, जिनकी डयूरेशन कम है और यील्ड ठीक होगा, मगर इनको पानी की आवश्यकता है। पल्सेज एक रेन फेड क्रॉप है, इसलिए जितना उत्पादन चाहिए, उतना नहीं होता है। वहां के किसानों का एक एटीट्यूड है कि जहां ज्यादा उत्पादन होगा, दो पैसे ज्यादा मिलेंगे, वे उधर जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज पल्सेज़ का उत्पादन कम है। मगर हमने Indian Council of Agricultural Research और एक international organisation, ICRISAT, दोनों को यह सूचना दी है कि आप अपना पूरा शोध इस पर कंसेंट्रेट करें। हमें इतने बड़े पैमाने पर पल्सेज़ इम्पोर्ट करने की स्थिति पिछले 9-10 सालों से आती रही है। इसमें कुछ-न-कुछ शोध करने की आवश्यकता है। हम इसके बारे में आशान्वित हैं।

श्री सभापति: श्री रवि शंकर प्रसाद। ...(**व्यवधान**)...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, मेरा सेकंड सप्लिमेंटरी भी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: सॉरी ...(**व्यवधान**)...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं। चांदनी चौक से आता हूं, सर। ...(**व्यवधान**)... मैं एक गरीब आदमी हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप उस लिस्ट में नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)... बिलो पॉवर्टी लाइन वालों की लिस्ट में आप नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, मेरा एक सवाल और है कि आजकल कुछ कमोडिटी एक्सचेंज खुले है, जिनमें ई-ट्रेडिंग होती है। पूरे साल में इतनी पैदावार नहीं होती, जितनी कि वे एक दिन में ट्रेडिंग कर देते हैं। सर, इससे लाखों परिवार बरबाद हो रहे हैं। हमारे यहां कई लोगों ने खुदकुशी की है। मैं यह जानना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने यहां पर कई अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों को होर्डिंग करने की इजाजत दे दी है। और उन्होंने बड़े-बड़े गोदाम खोल रखे हैं। इसमें दो चीजें हैं। पहला यह कि क्या आप ई-ट्रेडिंग बंद कराएंगे जिसका बहुत बुरा असर बाजार पर पड़ रहा है? दूसरा, उनकी कीमतों के ऊपर आपकी क्या पाबंदी है कि कितना अनाज वे अपने गोदामों में रख सकते हैं और उनके ऊपर आपका क्या अंकुश है?

श्री शरद पवार: ट्रेडिंग के बारे में रोक लगाने का सुझाव अग्रवाल जी देते हैं, बड़ी अच्छी बात है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: नहीं, सर, ई-ट्रेडिंग। सर, दोनों चीजों में फर्क है। जो कम्प्यूटर एक्सचेंज खुले हैं वह अलग चीज है, वह ट्रेडिंग नहीं कहलाएगी।

श्री सभापति: ठीक है उनको बोलने दीजिए। वे समझ नहीं पर रहे हैं अलग-अलग चीजों को।

श्री शरद पवार: जहां तक फ्यूचर मार्केट है, इस कंसेप्ट की शुरूआत अपने देश से हुई और दुनिया में गई है। मगर पिछले कई सालों में फ्यूचर मार्केट के बारे में यहां कुछ काम होता नहीं था। इस पर रोक लगाई गई थी चार साल पहले। भारत सरकार ने इस बारे में निर्णय ले लिया और अपने देश में भी किसानों को ठीक तरह से प्राइस रिएलाइजेशन होने के लिए यह फ्यूचर ट्रेडिंग इंट्रोडक्शन किया और पिछले दो-तीन साल से शुरू है। यह बात सच है कि इस साल जब कई चीजों की कीमतें ज्यादा ऊपर गईं तब एक बात हमारे सामने यह आई कि एक्च्युअली एवेलेबिलिटी रहते बिना इस पर ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा है और इसलिए इस पर कुछ ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत थी। रेस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार गवर्नमेंट को नहीं है, इसके लिए रेग्यूलेटर है। उनके साथ बातचीत करके कुछ रेस्ट्रिक्शन अभी लगाए और इसका असर ठीक तरह से हुआ है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, मेरा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों वाला जवाब रह गया।

श्री सभापति: वह नहीं देंगे जवाब।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, माननीय मंत्री जी के उत्तर को देखने से मुझे लगता हैं कि हम पी॰एल॰ 480 के समय में वापिस जा रहे हैं कि बाहर से इंपोर्ट होगा तो कीमतें कम होंगी। माननीय मंत्री जी, अगर मैं आपके उत्तर को दिखाने की कोशिश करूं जिसमें आपने कहा है कि

पैदावार कम हुई है, लेकिन अगर आप शुगर की बात करें तो 2005-06 में 278.3 मिलियन टन है, जो 2004-2005 से ज्यादा है, तो अगर आप ही के उत्तर के तर्क को मान लिया जाए तो फिर चीनी का दाम क्यों बढ़ रहा है। ...(व्यवधान)...

तो मेरा कहना यह है कि आपके उत्तर में विरोधाभास है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा है कि दाम कुछ महीनों से बढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, क्षमा करिए आप अनुभवी प्रशासक हैं, दाम पिछले एक वर्ष से अधिक से बढ़ रहे हैं। आपसे मेरा सवाल दो पार्ट में है। पहला पार्ट, जब इतने लम्बे समय से चल रहा है तो क्या हमारा कीमतों को रोकने का प्रयास सिर्फ इंपोर्ट पर आधारित है या आप कोई सुविचारित नीति कर रहे हैं? और दूसरा इसी का पार्ट है कि अगर आपके वर्तमान कदम प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं तो आम आदमी के लिए बनी आपकी सरकार इस दिशा में क्या कोई अन्य ठोस कार्रवाई करने वाली है?

श्री शरद पवार: जहां तक चीनी का सवाल आपने उठाया, यह बात सच है कि पिछले साल चीनी का उत्पादन देश में 120 लाख के आसपास था। जहां हमारी रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा है, जो 185 के आसपास है। मगर लास्ट ईयर हमारा उत्पादन बढ़ा है। और 190-192 के आसपास गया है। पिछले साल की जो कमी थी इसका असर थोड़ा बहुत इस पर था। दूसरे, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेज बहुत ऊपर गई हैं, तुरन्त कुछ कदम उठाने की आवश्यकता थी इसलिए यह कदम उठाया कि अभी इस देश में बाहर जो चीनी जाती थी उस पर रोक लगाई गयी और चीनी एक्सपोर्ट बैन्ड किया गया है। चीनी एक्सपोर्ट बैन्ड करने के बाद देश में चीनी के दाम नीचे लेवल पर आए हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद: क्षमा करिए, मंत्री जी, यह सच्चाई नहीं है। चीनी अभी भी महंगी है, आप बाजार में चलिए मेरे साथ, दिल्ली के बाजार में चलिए, मुम्बई में चलिए, पटना चलिए। चीनी महंगी है अभी।

श्री सभापति: आप भी बाजार में नहीं जाते, ये भी नहीं जाते।

श्री शरद पवार: जहां तक पल्सेज की बात है, तो पल्सेज के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाई गई है। क्योंकि यहां की एवेलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए और यहां की कीमतें नीचे आनी चाहिए। इसलिए लौंग टर्म और शौर्ट टर्म दोनों ही कदम उठाए गए हैं। आपने जो पी॰एल॰ 480 का सवाल यहां उठाया, एक बात सदन के सामने लाना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि अपने देश में जो गेहूं है, गेहूं का उत्पादन पंजाब, हरियाणा और यू॰पी॰ तथा यू॰ पी॰ में भी वेस्टर्न यू॰पी॰ जहां सबसे ज्यादा होता है, बाकी जगहों पर थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में होता है, बिहार में होता है, या गुजरात में होता है, बाकी राज्यों में होता नहीं है और जिस तरह से गेहूं के बारे में लोगों की

डिमांड बढ़ रही है, पौपुलशन बढ़ रही है, अगर ऐसी स्थिति रहेगी और प्रोडक्शन स्टेगनेंट रहेगा और दो तीन साल के बाद इस देश में गेहूं की समस्या बड़ी गंभीर बन सकती है, इसलिए इस बारे में हमने, जैसे बिहार जैसा राज्य है, मध्य प्रदेश जैसा राज्य है, गुजरात जैसा राज्य है और राजस्थान का कुछ एरिया है, वहां गेहूं का प्रोडक्शन कैसे ज्यादा हो सकता है, इसके बारे में हम एक और अलग तरीके की स्कीम तैयार कर रहे हैं जिससे इसका एरिया बढ़े जो देश की आवश्यकता है, वह पूरी हो जाये।

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, there is a demand made by the National Commission on Agriculture to include cereals in the Public Distribution System. It will help the farmers and will also create multinational Value. Will the Minister consider the demand made by the National Commission on Agriculture to include cerals and distribute them through the Public Distribution System?

श्री शरद पवार: सर, स्पेशली कोर्स ग्रेस, सिरियल्स में कोर्स ग्रेन्स के बारे में डिस्ट्रिब्यूशन करने की आवश्यकता है, यह सुझाव फारमर्स कमीशन का आया है, यह बात सच है। इस देश में इससे पहले कई राज्यों में कोर्स ग्रेन्स का ज्यादा इस्तेमाल होता था, मगर आजकल इसकी ठीक तरह से डिमांड नहीं आ रही है हमने कई राज्यों को यह लिखा है कि आज गेहूं का स्थिति ठीक नहीं है, हमारे पास बाजरा है, हमारा पास रागी है, हमारे पास ज्वार है और इन तीनों का डिस्ट्रिब्युशन पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में करने की तैयारी सरकार की हो, तो हम तीनों चीजों को देने के लिए तैयार हैं। मगर इस बारे में ठीक तरह से स्टेटों का रेसपांस नहीं आया है कल ही कैबिनेट ने एक डिसिज़न लिया है कि इस साल हम ज्वार, बाजरा और रागी को 50 रुपया ज्यादा बोनस देकर खरीदना चाहते हैं, मगर इसकी एक कंडिशन है कि हम इसे जिस राज्य से खरीदेंगे, उस राज्य को पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में उसको डिस्ट्रिब्यूट करने की तैयारी रखनी होगी। वह ऐसा करेंगे, तो इसकी प्रोक्योरमेंट भी बढ़ेगी और इसकी एवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी।

श्री मोतिउर रहमान: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दाल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, क्या मंत्री जी या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि सारी दाल नेपाल बार्डर से चाइना की तरफ स्मगल होकर जा रही है और उसको रोकने की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? गेहूं, चावल और सारी सामग्री नेपाल के रास्ते चाइना ती तरफ जा रही है, सरकार इसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री शरद पवार: सर, जहां तक चाइना की बात है, मैंने अभी तक ऐसी बात सुनी नहीं है, कोई इन्फोरमेशन दी जायेगी, तो इस पर हम ध्यान देंगे।

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Hon. Minister, your answer to this question talks about increasing the domestic supply through imports and asking the States to take specific steps. Sir, as you know, the Congress Working Committee and the Ministers, in their meetings, talked about extending the Public Distribution System. The news that has come out in the newspapers is that the Government is thinking of actually cutting the Public Distribution System in different areas and not taking into account the demand that is coming from this floor that not only the Public Distribution System should be expanded but other items like coarse grains, sugar etc., should also be increased in that allocation. Would the Minister be able to assure the House (a) that the Public Distribution System is not going to be cut and (b) that the Public Distribution System will be extended, if necessary, through importing wheat?

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, the Public Distribution System will definitely continue, but a targeted approach has been taken. It is our responsibility to protect the interests of the section which is really poor, which is vulnerable, and there is no compromise on that. There will not be reduction in their quota; there will not be reduction in the allocation, but, simultaneously, if there is a diversion, and that too for various reasons, then it is our responsibility to keep a close eye and stop that diversion and to also see that it reaches the proper sections.

जहां तक चीनी आदि का स्वीकार करने का प्रस्ताव है, वह अभी तक सरकार के सामने नहीं है, व्हीट और राइस की पूरी जिम्मेदारी ली है।

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, जब मंहगाई पर चर्चा हो रही थी तो माननीय मंत्री जी यहां नहीं थे। जो महंगाई है, उसको दूर करना बहुत ज्यादा शरद पवार जी के हाथ में है। यह सवाल महंगाई पर है। जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टरी है, वह भी आपके हाथ में है। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टरी में दाम लगातार आपके पास आते हैं। महंगाई रोकने के लिए, ठीक रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए केबिनेट सेक्रेटरी के अंडर एक कमेटी बनी थी, केबिनेट सेक्रेटरी जिसके अध्यक्ष होते हैं। उसकी मीटिंग कितनी बार हुई है? वृंदा कारत जी ने सवाल पूछा था तथा बाकी सदस्यों ने भी पूछा था कि भारत सरकार के हाथ में monopoly procurement था। आपके आगमन के बाद आपने, एशियन व्हीट बोर्ड है, कारगिल है, आईटीसी है, इनको खरीद के लिए कहा। आपके व्यापारी केवल मंडी में खरीद सकते हैं। इन लोगों को गांव-गांव जाकर खरीदने का अधिकार है। यह भी जान लीजिए कि

आपका विचार यह है कि प्राइवेट लोगों को देने के बाद किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा तो निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह दाम कितना ज्यादा मिल रहा है। उसके चलते गेहूं में आपका स्टॉक कम हुआ है, यानी आपके गोदाम खाली पड़े हैं जिसमें देश का अरबों रुपया खर्च हुआ है। जो पीडीएस है सभापति महोदय, आप तो पीडीएस के मामले में बहुत बेचैन रहे हैं और लगातार इस सदन में जिस तरह से चिंता आपने व्यक्त की है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पीडीएस पर खाद्य मंत्रियों को बुलाने से काम नहीं चलेगा, इस संबंध में आप मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाएं क्योंकि डेढ़ सौ लाख मीट्रिक टन गरीब आदमी के पास जाता है। पीडीएस सिस्टम साउथ में, सदर्न इंडिया में ठीक है, नॉर्थ इंडिया में ठीक नहीं है। ये तीन कारण है। एक तो monopoly procurement भारत सरकार के हाथ में था, जो एफसीआई खरीदती थी और डीसेंट्रलाइज़ करती थी। पीडीएस पर ध्यान देने की जरूरत है। कमोडिटी एक्सचेंज में जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग करते हैं, उनके चलते दाम बढ़े हैं। ये तीन कारण हैं। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कमोडिटी एक्सचेंज को हमने इसलिए शुरू किया था कि किसान को लाभ मिलेगा लेकिन लाभ नहीं मिला। एसेंशियल कमोडिटी को या तो बंद कीजिए, या निकाल दीजिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। मैंने मंत्री जी से तीन सवाल पूछे हैं।

श्री शरद पवार: कमोडिटी एक्सचेंज का डिसीज़न आपने लिया था और बहुत समझदारी से लिया था।

श्री शरद यादव: मैंने मान लिया। मंत्री जी, मैं इस सदन में बोला, आप यहां थे नहीं। मैंने कहा था कि मुझे परस्यू किया गया था कि किसानों को लाभ मिलेगा। अब यह पता चल गया कि इन्होंने 650 का गेहूं जो है, वह नौ सौ, साढ़े नौ सौ में बेचा है। इसके बाद क्या देखना हैं? मैं गलती मानता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि आप उस गलती में सुधार करें।

श्री शरद पवार: अभी हम इसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं लेकिन इसमें अगर कोई गलत काम होगा तो उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। टोटल बंद कर देना ...(व्यवधान)..

श्रीमती वृंदा कारत: सर,एसेंशियल कमोडिटीज़ में ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: क्या बात कर रहे हैं, क्या ध्यान देंगे? ...(व्यवधान)... उसमें कुछ है ही नहीं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: उन्हें बोलने दीजिए प्लीज़। ...(व्यवधान)... Please don't disturb.

श्री शरद यादव: क्या ध्यान देंगे आप? ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारत: सर, एसेंशियल कमोडिटीज़ को फ्यूचर ट्रेडिंग से हटाने की ...(**व्यवधान**)..

श्री सभापति: वह ठीक है, हो गया। क्वेश्चन यह नहीं है। ..(**व्यवधान**)..

श्री शरद यादव: ऐसा नहीं हो सकता है। ..(**व्यवधान**)..

श्रीमती वृंदा कारत: ऐसे कैसे हो सकता है? ..(**व्यवधान**)..

श्री सभापति: हो क्या सकता है, आप जवाब तो सुनिए। ..(**व्यवधान**)..

श्री शरद यादव: सर, यह महंगाई का सवाल है..(**व्यवधान**)..

श्री सभापति: आप पूरा जवाब तो सुनिए। ..(**व्यवधान**)..

श्री शरद यादव: वे कह रहे हैं कि ..(**व्यवधान**).. इनके हाथ में है कि उसको तत्काल वापस करें। ..(**व्यवधान**).. ये जानते हैं कि दाम बढ़ा है। ये वहां मुम्बई के रहने वाले हैं, इनको मालूम है। ..(**व्यवधान**).. कहो तो मैं उन दो तीन लागों का नाम बता सकता हूं।

श्री शरद पवार: जहां तक एपीएमसी का शरद जी ने बतलाया है, इससे पहले इस देश में monopoly procurement थी, यह बात सच नहीं है। हमारे देश में monopoly procurement स्कीम सिर्फ कॉटन के लिए महाराष्ट्र में हुई थी, बाकी किसी राज्य में अनाज के बारे में, मोनोपोली यानी खाली गवर्नमेंट ही परचेज़ करेगी, ऐसी स्कीम इससे पहले नहीं थी, आज भी नहीं है। जहां तक एपीएमसी एक्ट में सुधार करने की बात है, यह बात सच है कि चार साल पहले भारत सरकार ने मॉडल एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्कैटिंग कमॉडिटीज़ एक्ट तैयार किया और सभी स्टेट्स को भेजा। सभी स्टेट्स को इसमें सुधार करने के लिए कहा गया। आज 22 राज्यों ने इसमें सुधार किया है। इसमें सुधार से पहले किसानों को अपनी उपज मंडी में जाकर लाइसेंस वाले आढ़तियों और व्यापारियों को ही बेचने का अधिकार था। आज 22 राज्यों ने जो परिवर्तन किया है, उसमें ऐसा किया है कि जो किसान अपनी पैदावार करता है, उसे इस देश में कहीं भी अपनी पैदावार को बेचने का अधिकार है और जो उनको दो पैसे ज्यादा देता है, उसको वह माल उनको बेचने का अधिकार है।

श्री सभापति: बीच में मेरा भी क्वेश्चन है, इससे प्रोक्योरमेंट कम हुआ है, यह बात तो सही है न?

श्री शरद पवार: यह बिल्कुल बराबर है।

श्री सभापति: तो प्रोक्योरमेंट ज्यादा कैसे हो, इसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है?

श्री शरद पवार: यह प्रोक्योरमेंट कम हुआ, इसलिए क्योंकि यह परिवर्तन होने के बाद, यह जो बात यहां बतलाई गई है, यह सच है कि some of the traders have practically gone to the villages और वहां गांव में जाकर किसानों का माल ..(व्यवधान).. एम॰एन॰सी॰ का भी और इनके टोटल प्रोक्योरमेंट का भी हमने हिसाब-किताब कलेक्ट किया है, उन्होंने कुछ माल खरीदा है, यह बात सच है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में खरीदा है, यह बात भी सच है, मगर यह बड़े पैमाने पर है, यह बात सच नहीं है, यह लिमिटेड है। मगर वह खरीदेगा, क्योंकि अभी सभी को मौका दिया गया है और इसमें जहां तक किसानों की बात है, किसानों की फीलिंग है कि मुझे इसमें मेरे खेत से माल मंडी तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आती थी, ऑक्ट्राय आता था, तो यह सब सेविंग मेरी हो गई। मेरे दरवाजे पर आकर आज परचेज़ करना शुरू हो गया है और मुझे दो पैसे एम॰एस॰पी॰ से आज ज्यादा देते हैं। ऐसी स्थिति में आगे ऐसी परिस्थिति नहीं आनी हो, तो हमें दो डिसीज़न लेने पड़ेंगे। एक डिसीजन यह कि मिमिनम सपोर्ट प्राइस - यह तो कंटीन्यू करना ही पड़ेगा, जहां डिस्ट्रैस है, वहां सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर हम प्रोक्योर करेंगे और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हम अमल करेंगे, यह बात इससे आगे नहीं चलेगी। प्रिवेलिंग मार्केट रेट किसानों को अपनी उपज के लिए सरकार को देना होगा और इस तरह के प्रोपोज़ल के बारे में हम सोच रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: सभापति जी, जो जवाब है, वह ठीक आना चाहिए। भारत सरकार को छोड़कर किसानों से कोई खरीदता नहीं था। डीसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था। आपने ठीक बात कही कि जो इस बार आपने छूट दी है, तो आपके मानस में यह है कि दूसरे लोग आएंगे, तो किसान को ज्यादा मिलेगा। आप सर्वे करा लीजिए कि जो दूसरे लोगों को आपने दिया है, उसमें एक रुपया, डेढ़ रुपया, दो रुपया -कितना दिया है? वह भी तो आपको बताना चाहिए और मोनोपोली प्रोक्योरमेंट उसका नाम नहीं है। लेकिन भारत सरकार और पांच-छः स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए मैंने खुद ही अनुमति दी थी कि डीसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट करें। मैं यह निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि दोनों चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। आपके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट और कंज्यूमर अफेयर्स भी है। ये देश की महंगाई का सबसे बड़ा आपके पास ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: यादव साहब, ठीक है, आप इस पर विचार कर लीजिएगा। ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: आप जो मोनोपोली प्रोक्योरमेंट को कह रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारत: सर, यह बहुत सीरियस सवाल है।

श्री सभापति: ठीक है, इस पर विचार करेंगे, मैंने कह दिया है। ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: आप तो खुद ही गंभीर रहते हो इस विषय पर। आप खुद ही चिंतित रहते हैं, तो इस पर ठीक से जवाब तो उनको देना चाहिए?

श्री सभापति: गंभीर सभी हैं। श्री ए॰के॰ अंतोनी, बोलिए। ...(व्यवधान)... देखिए, हो गया है। ठीक है, इसके मामले में डिबेट होगी। पूरे दिन डिबेट होगी। अब आप क्वेश्चन्स करते जाएंगे, तो दूसरे क्वेश्चन्स नहीं आ पाएंगे। ...(व्यवधान)... अंतोनी जी, बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारत: सर कोई डिसीजन तो कराइए। ...(व्यवधान)... आप आश्वासन दीजिए सर।

SHRI N. JOTHI: Sir, we should have a discussion on this.

MR.CHAIRMAN: You give notice for discussion.

SHRI A.K. ANTONY: Sir, it is a well-known fact that whenever there is scarcity, always a large scale hoarding takes place. One of the reasons for the recent price rise is large scale hoarding by black-marketeers maybe, by traders and recently by even the multi-national companies. So when this question was discussed in the meeting of Chief Ministers, they said that they have no power after the revocation of the Essential Commodities Act. Considering this question, I would like to know whether the Government is again willing to - I am told that by an executive order the Government can restore the Essential Commodities Act - restore the Essential Commodities Act. If you can again bring in the Essential Commodities Act, that will give more powers to the State Governments. They can act against the hoarders. That will have salutary effect on the prices.

SHRI SHARAD PAWAR: It is surprising that some Chief Ministers have complained about it. At least, I am not fully aware of it. I will be happy to get this information. I would like to bring to the notice of the House that in 2002, a meeting of the State Chief Ministers was called. In that meeting, it was decided that we should reduce the number of items under the Essential Commodities Act. This was the recommendation of the Chief Ministers in that meeting. Secondly, the Standing Committee on Food has recently recommended कि आज जो सात आइटम्स हैं, वे सात से भी कम करो। यह कम करने का सुझाव यूनैनिमसली स्टैंडिंग कमेटी ने

दिया है। इसलिए इस बारे में यदि आज कुछ कदम उठाना हो और सुधार करना हो, तो जिस फोर्म ने यह सलाह दी है, उनके पास हमें जाना पड़ेगा। उनकी मीटिंग बुलाने के लिए और उनकी सलाह लेने के लिए मेरी तैयारी रहेगी।

Relief package for suicide prone areas

*83. SHRI VARINDER SINGH BAJWA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether any relief package has been announced for the suicide prone areas in the country for the benefit of farmers; and

(b) if so, the districts likely to be covered under that package?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) A special package for mitigating the stress of farmers for the six districts of Vidarbha region of Maharashtra, namely, Wardha, Yevatmal, Amravati, Akola, Buldana, and Washim, was announced by the Prime Minister during his visit of the region from 30th June to 1st July, 2006. The package aims at establishing a sustainable and viable farming and livelihood support system through debt relief to farmers, improved supply of institutional credit, non crop centric and integrated approach to agriculture, assured irrigation facilities, watershed management, better extension and farming support services, improved marketing facilities and subsidiary income opportunities through horticulture, livestock, dairying, fisheries, etc.

The Government is working out the rehabilitation package for the identified districts in the States of Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala on the lines of the package that has been announced for the Vidarbha region of Maharashtra. The districts to be covered in these three States are:

Karnataka - 6 Districts

- Belgaum, Hasan, Chitradurga, Chikmagalur, Kodagu and Shimoga.